

प्रेषक,

आर0डी0पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्श,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

महाप्रशासक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 21 जनवरी, 2008

विषय- महाप्रशासक कार्यालय हेतु सृजित 08 अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 189/xxxvi(1)एक/07-582/2001 दिनांक 23 अप्रैल, 2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, महाप्रशासक कार्यालय हेतु सृजित 08 अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, दिनांक 1-3-2008 से 28-2-2009 तक बढ़ाये जाने की सहमति स्वीकृति प्रदान करते हैं । उक्त पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या- 15- एक (1) / न्याय अनुभाग/03 दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा किया गया था ।

2- उक्त न्यायालयों के कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मधारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होंगी ।

3- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-07-महाप्रशासक कार्यालय नैनीताल-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामों जाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- ए-1-1270/78-दस, दिनांक 20 जुलाई, 1988 सम्पठित कार्यालय ज्ञाप संख्या- ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 7-11-92 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधित्वित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव,

संख्या- 34 (1)/xxxvi(1)एक/08-582/01

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड गाजरा, देहरादून ।
- 2- महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
- 4- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0रौ0/गार्ड फाईल ।

✓

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव,